रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 26, 1979/ज्येष्ठ 5, 1901
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 26, 1979/JYAISTHA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1979

का०आ० 1696.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 71-गोपालपुरम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बी० पमुलय्या, मार्फत श्री बसारी भास्कर राव, गोपालपुरम, तालुक कोव्वुर, जिला पश्चिम गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, उक्त उम्मीदवार द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बी० पमुलय्या को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ०प्र०-वि०स०/71/78(26)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 3rd April, 1979

S.O. 1696.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri B. Pamulayya, C/o Shri Dasari Bhaskara Rao, Gopalapuram, Taluk Kovvur, District West Godavari (Andhra Pradesh), a contesting candidate for General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 71-Gopalapuram constituency, has failed to lodge the account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the fai ure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri B. Pamulayya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/71/78(26)]

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1979

का०आ० 1697.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 207-हिमायत नगर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मानिक राव, म० सं० 3-4-916, निम्बोली अड्डा, काचीगूडा हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मानिक राव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० आ०प्र०-वि०स०/207/78(27)]

ORDER

New Delhi, the 6th April, 1979

S. O. 1697.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Manik Rao, H. No. 3-4-916, Nimboli Adda, Kachiguda, Hyderabad (Andhra Pradesh), a contesting candidate for General Election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in February, 1978 from 207-Himayatnagar constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Manik Rao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. AP-LA/207/78(27)]

आदेश

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1979

का० आ० 1698.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 242, अरवल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रंगबहादुर सिंह, ग्राम मुरादपुर हुजरा, टोला कागजी महल्ला, पोस्ट बैदराबाद, जिला गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपने अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रंगबहादुर सिंह को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/242/77(12)]

वी० नागसुब्रमण्यन सचिव

ORDER

New Delhi, the 12th April, 1979

S. O. 1698.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rang Bahadur Singh, Village Muradpur Huzara, Tola Kaganji Mahalla, P.O. Baidrabad, District Gaya, Bihar, a contesting candidate for General Election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 242-Arwal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And Whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, Therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rang Bahadur Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/242/77 (12)]

V. N. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

का०आ० 1699.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 242-अरवल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सकल देव सिंह, ग्राम-दौलतपुर, थाना-जहानाबाद, पोस्ट मोकर, जिला-गया (बिहार) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सकलदेव सिंह को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/242/77(13)]

ORDER

S. O. 1699.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sakaldeo Singh, Village Dalatpur, P. S. Jehanabad. P. O. Mokar, District Gaya (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June, 1977 from 242-Arwal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And Whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sakaldeo Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/242/77/(13)]

आदेश

का० आ० 1700.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून 1977 में बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 242-अरवल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सोहर लाल ग्राम-चोहर, पोस्ट-आनन्दपुर, जिला-गया (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में सफल रहे हैं,

यत: और, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सोहर लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/242/77(14)]

ORDER

S. O. 1700.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sohar Lal, Village Chohar, P. O. Anandpur, District Gaya (Bihar), a contesting candidate for general election to the Bihar Legislative Assembly held in June 1977 from 242-Arwal constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sohar Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/242/77(14)]

आदेश

का०आ० 1701.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 267-रामगढ़, निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रिझुनाथ चौधरी, ग्राम-सांडी, पोस्ट-सांडी, थाना-रामगढ़, जिला-हजारीबाग (बिहार), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रिझुनाथ चौधरी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/267/77(15)]

ORDER

S. O. 1701.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rijhunath Choudhary, Village and P.O. Sandi, Thana Ramgarh, District Hazaribagh (Bihar) a contesting candidate for general election to the Bihar Legsilative Assembly held in June, 1977 from 267-Ramgarh constituency, has failed to lodge an account of his election evpenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the Said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rijhunath Choudhary to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. BR-LA/267/77(15)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1979

का०आ० 1702.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1978 में हुए मिजोरम विधान परिषद के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 25-लुंगफो निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एच० सनगहुंगा, तुइकुआल वेंग, डाक० एवं जिला ऐजल (मिजोरम) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उन्होंने इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास उस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एच० संगहुंगा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० मिजो०-वि०स०/25/78]

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1979

S. O. 1702.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri H. Sanghlunga, Tuikual Veng. P.O. Aizawal, District Aizawal (Mizoram) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1978, from 25-Lungpho Constituency has failed to lodge an account of his elec-

tion expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri H. Sangkunga to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MIZ-LA/25/78]

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1979

का०आ० 1703.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-गूलेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कुलदीप सिंह, ग्राम बन अटरियां, पो० आ० कण्डेरीडा, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचलप्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कुलदीप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हि०प्र०-वि०स०/37/77(1)]

ORDER

New Delhi the 26th April, 1979

S.O. 1703.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kuldip Singh, Village Ban, Atahrian, P.O. Kandorori, Teh. Nurpur District Kangra, a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 37-Guler constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kuldip Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HP-LA/37/77(1)]

आदेश

का०आ० 1704.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-गूलेर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मनीराम, ग्राम लैव, पो०आ०जवाली, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मनीराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हि०प्र०-वि०स०/37/77(2)]

ORDER

S.O. 1704.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mani Ram, Village Lale. P.O. Jawali, Teh. Nurpur, District Kangra, a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 37-Guler constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mani Ram to be disqualified for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of the order,

[No. HP-LA/37/77(2)]

आदेश

का०आ० 1705—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि हिमाचल प्रदेश में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 41-थुरल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री प्यारे लाल, गांव बरोटाजगीर, डा० गगवूही, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री प्यारे लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है;

[सं० हि०प्र०-वि०स०/41/77(3)]

ORDER

S.O. 1705.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pyare Lal, Village Barata Jaggir, P. O. Garuhi, Teh. Dehra, Distt. Kangra a contesting candidate for general election to the Himachal Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 41-Thural constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And Whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pyare Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HP-LA/41/77(3)]

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

का॰आ॰ 1706.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, गुजरात सरकार के परामर्श से श्री आर॰वी॰ चन्द्रमौली के छुट्टी पर चले जाने पर उनके स्थान पर श्री बी॰सी॰मारू, संयुक्त मुख्य निर्वाचन आफिसर तथा संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को उनके कार्यभार सम्भालने की तारीख से अगले आदेशों तक गुजरात राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतदद्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं॰ 154/गुजरात/79]

New Delhi the 1st May, 1979

S.O. 1706.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Gujarat hereby nominates Shri B. C. Maru, Joint Chief Electoral Officer and Joint Secretary to Government, General Administration Department as the Chief Electoral Officer for the state of Gujarat with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri R. V. Chandramouli proceeded on leave.

[No. 154/GJ/79]

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1979

का॰आ॰ 1707.—यतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 188-थिरुविडामरुडु निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के॰ नेडुनचेजियान, अध्यक्ष, नगरासामपेट्टय पंचायत, नगरासामपेट्टाय, जिला थन्जावुर (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं, ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री के॰ नेडुनचेजियान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं॰ त॰ना॰-वि॰स॰/188/77(35)]

ORDER

New Delhi, the 4th May, 1979

S.O. 1707.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. Nedunchezian, President, Nagarasampettai Panchayat, Nagarasampettai, Thanjavur District, (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu legislative assembly held in June, 1977 from 188-Thiruvidamarudui assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he/has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri/K. Nedunchezian to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assemb'y or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/188/77(35)]

आदेश

का॰आ॰ 1708.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए कर्नाटक विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 160-भद्रावती निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चोक्कलिंगम, एन॰एम॰सी॰, मेन स्ट्रीट, I क्रास, भोवी कालोनी, ओल्ड टाउन, भद्रावती, जिला शिमोगा (कर्नाटक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उस के पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री चोक्कालिंगम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं॰ कर्नाटक-वि॰स॰/160/78(6)]

ORDER

S.O. 1708.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chokkalingam, N. M. C. Main Street, I Cross, Bhovi Colony, Old Town, Bhadravati, District Shimoga (Karnataka), a contesting candidate for general election to the Karnataka legislative assembly held in February, 1978 from 160-Bhadravathi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chokkalingam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

By order,

[No. KT-LA/160/78(6)]

आदेश

नई दिल्ली, 14 मई, 1979

का॰आ॰ 1709.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 179-गंगाखेड़ (अ॰जा॰) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मालसे वाल्मिराम नागोजी मकान जैकवाडी प्रोजैक्ट, कैनाल बर्क, प्रभराय कैम्प, डाकघर ग्राम-ठार पनर्गा, तालुक परभनी, जिला परभनी महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सालवे बालीराम नागोजी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा०-वि०स०/176/78(128)]

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव

ORDER

New Delhi, the 14th May, 1979

S.O. 1709.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Salve Baliram Nagoji C/o Jaikwadi Project, Canal work, Amrai Camp, Post Office : Village Tad-Pangri, Taluk Parbhani, District Parbhani a contesting candidate for General Election to the Maharashtra Legislative Assembly held in February, 1978 from 176-Gangakhed (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commmission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Salve Baliram Nagoji to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/176/78(128)]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 1979

का० आ० 1710.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पंजाब विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-पक्का कलां (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जुगराज सिंह, ग्राम व डा० झुम्बा, तहसील व जिला भटिंडा (पंजाब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जुगराज सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० पंजाब वि०स०/110/77]

ORDER

New Delhi, the 3rd May, 1979

S.O. 1710.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jugraj Singh Village and P. O. Jhumba, Tehsil and District Bhatinda (Punjab) a contesting candidate for general election to the Punjab Legislative Assembly held in June, 1977 from 110-Pakka Kalan (SC) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the fallure;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shri Jugraj Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. PB-LA/110/77]

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1979

का०आ० 1711.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 257-खुटहन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बशिष्ट नारायण, ग्राम लवायन, डा० भगमलपुर, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बशिष्ट नारायण को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

[सं० उ०प्र०-वि०स०/257/77(4)]

ORDER

New Delhi, the 4th May, 1979

S.O. 1711.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bashist Narain, Village Lawain, P.O. Bhagmalpur, District Jaunpur (Uttar Pradesh), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 257-Khutahan constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bashist Narain to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/257/77(4)]

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का०आ० 1712.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 251-मझियाहू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बंशराज, ग्राम तथा पोस्ट गुतवन, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बंशराज को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/251/77(5)]

ORDER

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1712.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bans Raj, Village and Post Gutwan, Dist. Jaunpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 251-Marahu constituency, has gailed to lodge an account of has election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bans Raj to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/251/77(5)]

आदेश

का०आ० 1713.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 400-खेकड़ा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नेपालसिंह, ग्राम सकरपुरा, डाकखाना लोनी, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नेपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/400/77(6)]

ORDER

S.O. 1713.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nepal Singh, Village Sakarpur, P. O. Loni, District Meerut, Uttar Pradesh a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 400-Khekra constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nepal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/400/77(6)]

आदेश

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

का०आ० 1714.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 254-जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रईस अहमद, मोहल्ला बल्लोचटोला, पोस्ट सदर, जिला जौनपुर (उत्तर प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रईस अहमद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/254/77(7)]

ORDER

New Delhi, the 7th May, 1979

S.O. 1714.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raies Ahmed, Mohalla Balloch Tola, P. O. Sadar, District Jaunpur, Uttar Pradesh a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in June 1977 from 254-Jaunpur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajeu Ahmed to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/254/77(7)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1979

का०आ० 1715.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च 1977 में हुए लोक सभा उत्तर प्रदेश के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 83-कैराना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनस हुसैन पुत्र श्री, हामिद हुसैन, मोहल्ला खरादियान, कस्बा जलालाबाद जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनस हुसैन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स० /83/77(1)]

आर० डी० शर्मा अवर सचिव,

ORDER

New Delhi, the 8th May, 1979

S.O. 1715.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anas Husain S/o Shri Hamid Husain, Mohalla Kharadian, Jalalabad, District Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the House of the People Uttar Pradesh held in March, 1977 from 83-Kairana constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anas Husain to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/83/77(1)]

R. D. SHARMA, Under Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नोटिस

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का०आ० 1716.—इसके द्वारा लेख्य प्रमाणक नियम (नोटेरीज रुल्स), 1956 के नियम 6 के अनुसार, समक्ष प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है, कि उक्त प्राधिकारी को श्री मनमोहन सिंह सेठी, एडवोकेट, दिल्ली ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन, सारे भारत में लेख्य प्रमाणक (नोटेरी) का काम करने की नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति को लेख्य प्रमाणक के रूप में नियुक्ति के बारे में यदि कोई आपत्तियां हो तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के चौदह दिन के अन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को लिख कर भेज दिये जाये।

[सं० 22/39 /79-न्याय]

ल० द० हिन्दी, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

NOTICE

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1716.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Manmohan Singh Sethi Advocate, New Delhi for appointment as a Notary to practise in Union of India

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/39/79-JUS]

L. D. HINDI, Competent Authority

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का० आ० 1717.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में गृह मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिसके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली।
2. कार्यालय महानिरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस, नई दिल्ली

[सं० 12017/3/78-हिन्दी]

कैलाश शंकर कनकन, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1717.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Home Affairs, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Directorate General of Border Security Force, New Delhi.
2. Office of the Inspector General, Indo-Tibbet Border Police, New Delhi.

[No. 12017/3/78-Hindi]

K. C. KANKAN, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

का०आ० 1718.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती

है कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में फार्म 'क' में दिये गये नोट (च) के उपबन्ध निम्नलिखित बैंकों अर्थात् :—

1. इलाहाबाद बैंक
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
3. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
4. देना बैंक
5. युनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि०

पर 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार उनके तुलन-पत्र के बारे में लागू नहीं होंगे जो कि उक्त फार्म के सम्पत्ति और परिसम्पत्ति पक्ष की मद 4 के उप शीर्ष (ii), (iii), (iv) और (v) में से किसी एक के सामने दिये गये भीतरी कालम में दिखाई गई कीमतें जब उन उप-शीर्षों के अन्तर्गत दिये गये निवेशों के बाजार मूल्य से बढ़ जाती हैं तो उस उप-शीर्ष के अन्तर्गत दिखाये गये निवेशों के बाजार मूल्य कोष्ठक में अलग दिखलाता है ।

[सं० 15(9)-बी०ओ०-III/79]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 30th April, 1979

BANKING DIVISION

S.O. 1718.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the Form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks viz.

1. Allahabad Bank.
2. Union Bank of India
3. Central Bank of India
4. Dena Bank
5. United Industrial Bank Ltd.

in respect of their balance-sheet as at the 31st Decebber, 1978, which, when the value shown in the inner column against any of the sub-heads (ii), (iii), (iv) and (v) of item 4 of the Property and Assets side of the said Form exceeds the market value of the investments under that sub-head, shows separately within brackets the market value of the investments under that sub-head.

[No. 15(9)-B.O. III/79]

नई दिल्ली, 14 मई, 1979

का०आ० 1719.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध बैंक आफ तंजावूर लिमिटेड, तंजौर पर 28 मार्च, 1981 तक निम्नलिखित अचल सम्पत्तियों पर लागू नहीं होंगे :—

(1) ग्राम थेरकुवेली, चिदाम्बरम, जिला साउथ अर्काट, तमिलनाडु में स्थित भूमि जिसकी माप 3 एकड़ 15 सेंट है (क०सं० 74/2-डी-72, 74/3-डी-34, 77/1-डी-75, 53/7-1-34)

(2) ग्राम परमेश्वरनालूर, चिदाम्बरम, जिला साउथ अर्काट, तमिलनाडु में स्थित भूमि जिसकी माप 1 एकड़ और 29 सेंट हैं (क्रम संख्या 106/3-1-29) ।

[सं० 15(10)-बी०ओ० III/79]

मे०भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, 14th May, 1979

S.O. 1719.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply upto 28th March 1981 to the Bank of Thanjavur Ltd., Tanjore in respect of the following immovable properties :—

(i) Land measuring 3 acres and 15 cents in Therkuveli Village, Chidambaram, South Arcot District, Tamil Nadu (S. No. 74/2-D. 72; 74/3-D. 34; 77/1-D. 75; 53/7-1-34) and

(ii) Land measuring 1 acre and 29 cents in Parameswaranallur Village, Chidambaram, South Arcot District, Tamil Nadu (S. No. 106/3-1-29).

[No. 15(10)-B.O. III/79]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का०आ०. 1720.—मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 753 पर का०आ० 933 के अन्तर्गत प्रकाशित दिनांक 28 फरवरी, 1979 की अधिसूचना संख्या 8-8/79-ए०सी० के हिन्दी रूपान्तर में निम्नलिखित को जोड़कर/प्रतिस्थापित करके पढ़ा जाये—

(1) कोआपरेटिव बैंक के नाम में "सेंट्रल" शब्द को "भरवन" के बाद तथा "कोआपरेटिव" से पहले जोड़ दिया जाये।

(2) क्रम संख्या 2 में उल्लिखित गैर-बैंकिंग परिसम्पत्तियों में "मकान नं० 583" के स्थान पर "मकान नं० 5836" पढ़ा जाये।

(3) क्रम संख्या 3 में उल्लिखित गैर-बैंकिंग परिसम्पत्तियों में "संख्या 11" के स्थान पर "संख्या 15" पढ़ा जाये।

[सं० 8-8/79-ए०सी०]

यशवन्त राज, अवर सचिव

नई दिल्ली, 15 मई, 1979

का० आ० 1721.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे०एन० सक्सेना को 16 मई, 1979 से आरम्भ होने वाली तथा 30 जून, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का प्रबंध निदेशक पुनः नियुक्त करती है ।

[संख्या एफ 9/13/79-बी०ओ०-1(1)]

New Delhi, the 15th May, 1979

S.O. 1721.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) and of sub-section (2) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby re-appoints Shri J. N. Saxena as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India for the period commencing on the 16th May, 1979 and ending with the 30th June, 1979.

[No. F. 9/13/79-BO. I(1)]

का० आ० 1722.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री जे० एन० सक्सेना को, जो कि 16 मई, 1979 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक पुनः नियुक्त किये गये हैं उसी तारीख से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[संख्या एफ 9/13/79-बी०ओ० 1(2)]

बलदेव सिंह, संयुक्त सचिव

S.O. 1722.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, (18 of 1964), the Central Government hereby appoints Shri J. N. Saxena who has been re-appointed as the Managing Director of the Industrial Development Bank of India with effect from the 16th May, 1979, to be the Chairman of the Board of Directors of the Industrial Development Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/13/79-BO. I(2)]

BALDEV SINGH, Jt. Secy.

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1979

स्टाम्प

का० आ० 1723.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है, जो पंजाब वित्तीय निगम द्वारा 1978-79 के में किये गये पचपन लाख रु० मूल्य के डिबेंचरों (17वीं श्रृंखला) पर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं० 20/79 स्टाम्प फा०सं० 33/13/79-वि०का०]

एस०डी० रामस्वामी, अवर सचिव

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1979

STAMPS

S.O. 1723.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the debentures (17th Series) to the value of fifty-five lakhs of rupees, issued by the Punjab Financial Corporation, during 1978-79 are chargeable under the said Act.

[No. 20/79-Stamps-F. No. 33/13/79-ST]

S. D. RAMASWAMY, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

इलायची नियंत्रण

का०आ० 1724.—केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम 1966 के नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (च) के साथ पठित इलायची अधिनियम 1965 (1965 का 42) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित व्यक्ति को, स्तम्भ (2) में उल्लिखित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन स्थापित इलायची बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और विनिर्दिष्ट करती है कि वह इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 नवम्बर, 1981 तक पद धारण करेंगे :—

सारणी

(1)	(2)
श्री टी० नारायण चार तालका केरी, मादीकेरी तालुक, कुर्ग जिला।	ऐसे अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के प्रतिनिधि, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

[फा० सं० 32/6/78-प्लांट (बी)]

एस० महादेव अय्यर, उप-निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delhi, the 7th May, 1979

CARDAMOM CONTROL

S.O. 1724.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965) read with clause (f) of sub-rule (2) of rule 3 of the Cardamom Rules 1966, the Central Government hereby appoints the person mentioned in column (1) of the Table below to be a member of the Cardamom Board established under sub-section (1) of the said section, representing the category mentioned in column (2) thereof; and specifies that he shall hold office with effect from the date of the publication of this notification in the Official Gazette of India and upto the 15th November, 1981 :—

TABLE

(1)	(2)
Shri T. Narayana Char Talakaveri, Madikeri Taluk, Coorg District.	Representative of such other persons or class of persons who, in the opinion of the Central Government ought to be represented on the Board.

[File No. 32/6/78-PLANT(B)]

S. MAHADEVA IYER, Dy. Director

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात का कार्यालय)

आदेश

मद्रास, 23 मार्च, 1979

का० आ० 1725.—सर्वश्री राजगोपालन एण्ड कम्पनी, 9, वेंकटाचल मुदली स्ट्रीट, मद्रास-3 को अप्रैल-मार्च की अवधि के लिए होगस हेयर ब्रेस्सज सहित आर्टिस्टस ब्रेस्सज का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०ई०-0288934-सी-एक्स एक्स-65-एम-77 दिनांक 6-10-77 स्थापित आयातक श्रेणी के अन्तर्गत जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त लाइसेंस के मूल्य रुपये 5,000 रुपये में से रुपये 3460 तक का आयात करके, बाकी रुपये 1540 तक का अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदन किया है। अपने दावे के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है और लाइसेंस की मुद्राविनिमय नियंत्रण की प्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें आयात किये गये माल की रकम को सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने साक्ष्यांकित किया है।

मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि स्थापित आयातक श्रेणी के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०ई० 028893 4-सी-एक्सएक्स-65-एम-77-दिनांक 6-10-77 की सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो गयी/अस्थानस्थ हो गयी है और निदेश देता हूं कि आवेदक को उपर्युक्त आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। उपर्युक्त आयात लाइसेंस संख्या पी०ई०-0288934-सी-एक्स एक्स-65-एम-77 दिनांक 6-10-77 रुपये 5,000 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[सं० आईटी सी/731/96-01/06/ए० एम-78/ई आई]

(Office of the Deputy Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

Madras, the 23rd March, 1979

S.O. 1725.—M/s. Rajagopalan and Company, 9, Venkatachala Mudali Street, Madras-3 was issued with an import licence No. P/E/0288934/C/XX/65/M/77 dt. 6-10-77 under the Established Importer Catagory for import of Artists Brushes including Hogo Hair Brushes for AM. 78 period. The licencee has since applied for a duplicate copy of the above import licence only for an unutilised value of Rs. 1540/- after utilising the licence to the value of Rs. 3460 out of Rs. 5000. In support of their contension, the applicant has filed an affidavit and Exchange Control Copy of licence showing the utilised amount duly attested by the Customs Officials.

I am satisfied that the original customs copy of import licence No. P/E/0288934/C/XX/65/M/77 dt. 6-10-77 under the Established Importers Category has been lost/misplaced and direct that a duplicate copy of the above Customs Copy of import licence shall be issued to the applicant. The original copy of above licence Custom Copy of No. P/E/0288934/C/XX/65/M/77 dt. 6-10-77 for Rs. 5000 is hereby cancelled.

[ITC/731/96.01/06/A.M. 78/EI.]

आदेश

मद्रास, 10 मई, 1979

का० आ० 1726.—सर्वश्री शक्ति एक्स्ट्राक्ट्स कम्पनी, मेट्टूपालयम, तमिलनाडु-641301 को अप्रैल 78–मार्च 79 की अवधि के लिए पूंजीगत माल का आयात करने के लिए रुपये 7,41,845 का आयात लाइसेंस संख्या पी०सी० 2050024-सी-एक्स एक्स-68-एम-78 दिनांक 3-8-78 जारी किया गया था। लाइसेंसधारी के विशिष्ट निवेदन पर पूंजीगत माल आयात करने के लिए रुपये 6,96,335 का नये लाइसेंस संख्या पी सी 2050084-सी एक्स एक्स-70-एम-78 दिनांक 13-2-79 सर्वश्री एन सी अरोमेटिक्स लिमिटेड को जारी किया गया है।

इसलिए सर्वश्री शक्ति एक्स्ट्राक्ट्स कम्पनी, मेट्टूपालयम को जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०सी० 2050024-सी-एक्स एक्स-68-एम-78 दिनांक 3-8-78 को रद्द करता हूं।

[संख्या आई टी सी-सी जी : 8–ए एम-79–ए यू II]

आर० कुमारवेलु, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात

ORDER

Madras, the 10th May, 1979

S.O. 1726.—M/s. Sakthi Extracts Company, Metupalayam, Tamil Nadu-641301 were issued import licence No. P/C/2050024/C/XX/68/M/78, dated 3-8-1978 for Rs. 7.41,845 for import of machinery items for April, 1978—March, 1979 period on a specific request from the licensee a fresh licence bearing No. P/C/2050084/C/XX/70/M/78 dated 13-2-1979 for the import of Capital goods for a value of Rs. 6,96,335 had been issued, in favour of M/s. Encee Auromatics Limited, Mettupalayam.

I, therefore, cancel the licence No. P/C/2050024/C/XX/68/M/78, dated 3-8-1978 issued to the said M/s. Sakthi Extracts Company Mettupalayam.

[No. ITC/CG. 8/AM. 79/AU. II]

R. KUMARAVELU, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

for Jt. Chief Controller of Imports & Exports.

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1979

का० आ० 1727.—सर्वश्री दी प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली को लाइसेंस अवधि अप्रैल, 76 से मार्च, 77 के लिए मुद्रण और सम्बद्ध मशीन के आयात के लिए 3,86,000 रुपए (तीन लाख और छियासी हजार रुपए मात्र) का आयात लाइसेंस संख्या जी/टी/2420150/टी यू आर/58/एच/41-42, दिनांक 22 अप्रैल, 1977 प्रदान किया गया है।

2. अब फर्म ने उपयुक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क समाहर्ता, एयर कार्गो, पालम, नई दिल्ली के पास पंजीकृत कराने के पश्चात खो गई है और आंशिक रूप से उसका उपयोग किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि उपर्युक्त लाइसेंस कुल 3,86,000 रुपए की राशि के लिए जारी किया गया था और जिस राशि के लिए अब अनुलिपि लाइसेंस की आवश्यकता है, वह 2,60,066.41 रुपए है। फर्म ने इस बात की पुष्टि की है और घोषणा की है कि उक्त लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, धरोहर नहीं रखा गया है, हस्तांतरित नहीं किया गया है अथवा उनके द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी अन्य पार्टी को किसी भी प्रयोजन के लिए/विचार के लिए चाहे जो कुछ भी हो सम्भवतः सौंपा नहीं गया है और वह इस बात से सहमत है और वचन देते हैं कि यदि मूल लाइसेंस बाद में मिल जाएगा तो इस कार्यालय को रिकार्ड के लिए लौटा देंगे।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने 1978-79 को आयात-निर्यात क्रियाविधि हैण्डबुक के अध्याय-54 के पैरा 354 में अपेक्षित एक शपथपत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात-लाइसेंस संख्या जी/टी/2420/50/टी/यू आर/58/एच/41-42, दिनांक 22-4-77 की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक की लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति रद्द कर दी गई है।

4. आयात लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या सी जी-2/पी ई सी-1/67-5/75-76/एन पी एस]

आर० सी० एस० मेनन, उप मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Improts and Exports)

ORDER

New Delhi, the 7th April, 1979

S.O. 1727.—Messers The Project and Equipment Corporation of India Ltd., New Delhi, have been granted Import Licence No. G/T/2420150/T/UR/58/H/41-42 dated 22nd April, 1977 for Rs. 3,86,000 (Rupees Three Lakhs and Eighty-six thousand only) for import of Printing and Allied Machinery, for the licensing period April, 1976 to March, 1977.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the above licence on the ground that the original Customs Purposes Copy has been lost after having been registered with the Collector of Customs, Air Cargo Palam, New Delhi and has been utilised partly. They have also stated that the above licence has been issued for the total amount of Rs. 3,86,000 and the amount for which the duplicate licence now required is Rs. 2,60,066.41. The firm have affirmed and declared that the said licence has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by them or on their behalf to any other party for any purpose/consideration whatsoever and agrees and undertakes to return the original licence, if traced later, to this office for record.

3. In support of their contention the applicant have filed an affidavit, as required in Para 354 of Chapter LIV of Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes Copy of Import licence No. G/T/2420150/T/UR/58/H/41-42 dated 22-4-1977 has been lost and directs that duplicate copy of the Customs Purposes Copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes Copy of the licence has been cancelled.

4. The duplicate copy of Customs Purposes Copy of the Import Licence is being issued separately.

[File No. CG II/PEC-1/67-V/75-76/NPS]

R. C. S. MENON, Dy. Chief Controller of Imports and Exports for Chief Controller of Imports and Exports.

आदेश

नई दिल्ली, 8 मई, 1979

का० आ० 1728.—सर्वश्री डक्ट्रान कास्टिंग्स लि०, बी-15, औद्योगिक विकास क्षेत्र उप्पल, हैदराबाद-500039 को फ्रेंच क्रेडिट के अन्तर्गत

3,00,786 रुपए (तीन लाख सात सौ छियासी रुपए मात्र) का आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2210848, दिनांक 16-12-77 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस वित्त मंत्रालय द्वारा अस्थानस्थ हो गया/खो गया है । लाइसेंसधारी ने आगे यह बताया है कि लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना ही अस्थानस्थ हो गया/खो गया है ।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने सिकन्दराबाद में नोटरी के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथपत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2210848, दिनांक 16-12-77 खो गया है और निदेश देता है कि आवेदक को एक अनुलिपि लाइसेंस जारी किया जाए । मूल लाइसेंस रद्द किया जाता है ।

4. अनुलिपि लाइसेंस अलग से जारी किया जा रहा है ।

[संख्या-एससी/13(आरएम)/77-78/आरएम- I]

सी०एस० आर्य, उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 8th May, 1979

S.O. 1728.—M/s. Ductron Castings Ltd., B-15, Industrial Development Area Uppal, Hyderabad 50039 were granted import licence No. P/D/2210843 dated 16-12-77 under French Credit for Rs. 3,00,786 (Three Lakhs Seven Hundred & Eighty Six only).

2. The firm have requested for issue of duplicate copy of the above licence on the ground that the original licence has been misplaced//lost by the Ministry of Finance. It has been further reported by the licensee that the licence has been misplaced/lost without being registered at any Customs House and has not been utilised at all.

3. In support of their contention, the applicant have filed an Affidavit duly sworn in before a Notary in Secunderabad. The undersigned is satisfied that the original import licennce No. P/D/2210848 dated 16-12-77 has been lost and directs that a duplicate licence should be issued to the applicant. The original licence is cancelled.

4. The duplicate licence is being issued separately.

[No. SC/13(RM)/77-78/RM-I]

C.S. ARYA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 मई, 1979

(आय-कर)

का० आ० 1729.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ध की उप-धारा (2) के खंड (i) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्पैस्टिक्स सोसाइटी, अपर कोलाबा रोड, अफगान चर्च के सम्मुख, बम्बई-400005 को विकलांग व्यक्तियों की एक संस्था अधिसूचित करती है ।

[सं० एस-13020/5/79-एम एस०]

एन०ए० सुब्रामणी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 9th May, 1979

INCOME TAX

S.O. 1729.—In pursuance of clause (i) of sub-section (2) of section 80D of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the Spastics Society, Upper Colaba Road, Opp. Afghan Church, Bombay-400005, as an institution for the care of handicapped persons.

[No. S. 13020/5/79/MS]

N. A. SUBRAMONEY, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

का० आ० 1730.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानाल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है; और ग्राम बालंडा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) एरखिटा देहुरी सुपुत्र काशी देहुरी और

(2) वृन्दावन देहुरी सुपुत्र धीरा देहुरी

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 1.88 एकड़ या 0.76 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अस्थायी अधिकरण धेनकानाल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानाल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19/5/79-सी०एल(1)]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 7th May, 1979

S.O. 1730.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa).

And whereas (1) Arkhita Dehuri S/o Kashi Dehuri and (2) Brindaban Dehuri S/o Dhira Dehuri of village Balanda, the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 1.88 acres or 0.76 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(1)]

का० आ० 1731.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित करली है;

और ग्राम बालंदा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्:

(1) बेदा सवाई सुपुत्र चंटी सवाई और

(2) समन्तरा सवाई सुपुत्र स्वर्गीय कैरू सवाई

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 2.80 एकड़ या 1.13 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अणकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा।

[संख्या 19(5)/79-सी०एल० (3)]

S.O. 1731. Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa).

And whereas (1) Beda Sawain s|o Chanti Sawain and (2) Samantra Sawain s|o Late Kairu Sawain,

of village Balanda the ersons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 2.80 acres or 1.13 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interessted.

[No. 19(5)|79-CL(3)]

का० आ० 1732.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है;

और ग्राम बालंदा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) राघब बिसवाल सुपुत्र भजना बिसवाल और

(2) दुबाई बिसवाल सुपुत्र नुहरा बिसवाल

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.83 एकड़ या 0.33 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अणकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा।

[संख्या 19/5/79-सी० एल० (2)]

S.O. 1732.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa).

And whereas (1) Raghab Biswal s|o Bhajana Biswal and (2) Dubai Biswal s|o Nuhara Biswal,

of village Balanda the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.83 acres or 0.33 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interessted.

[No. 19(5)/79-CL(2)]

का० आ० 1733.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित करली है;

और ग्राम बालंदा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) चैतन बेहरा और

(2) जय बेहरा, दोनों सखाली बेहरा के पुत्र हैं,

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.32 एकड़ या 0.13 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों के संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अणकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० 4]

S.O. 1733.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa).

And whereas (1) Chaitan Behra and (2) Jai Behra both sons of Sankhali Behra.
of village Balanda the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the compenent authority for payment of compensation for area of 0.32 acres or 0.13 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(4)]

का० आ० 1734.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957(1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.35 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम बालंदा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) हरी कृष्ण बेहरा

(2) चौधरी बेहरा और

(3) बनमाली बेहरा, सभी गति कृष्ण बेहरा के पुत्र हैं,

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.43 एकड़ या 0.174 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा।

[संख्या 19/5/79-सी० एल० (5)]

S.O. 1734.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa).
And whereas (1) Hari Krishna Behra (2) Choudhary Behra

3) Banmali Behra all sons of Gati Krishna Behra.

of village Balanda the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.43 acrs of 0.174 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(5)]

का० आ० 1735.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित करली है ;

और ग्राम बालंदा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, (1) राहास बिहारी प्रधान (2) राघव प्रधान, दोनों दुलका प्रधान के पुत्र हैं, (3) गोबर्द्धन (4) भागीरथी प्रधान (5) मकरध्वज प्रधान, सभी अपोति प्रधान के पुत्र हैं, (6) लक्ष्मीधर प्रधान (7) भजना प्रधान (8) पुनिया प्रधान, सभी नटवर प्रधान के पुत्र हैं, (9) गनेश्वर प्रधान (10) श्यामधर प्रधान (11) सुधीर प्रधान, सभी सुरेन्द्र प्रधान के पुत्र हैं, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.32 एकड़ या 0.13 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० (6)]

S.O. 1735.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa).

And whereas (1) Rahas Bihari Pradhan (2) Raghab Pradhan, both sons of Dulak Pradhan (3) Gobardhan (4) Bhagirathi Pralhan (5) Makardhawaj Pradhan all sons of Aporti Pradhan (6) Laxmidhar Pradhan (7) Bhajana Pradhan (8) Punia Pradhan all sons of Natwar Pradhan (9) Ganeshwar Pradhan (10) Shyamdhar Pradhan (11) Sudhir Pradhan all sons of Surendra Pradhan of village Balanda, the persons interested, have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.32 acres or 0.13 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(6)]

का० आ० 1736.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम बालंदा से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, (1) अकरम भुटिया सुपुत्र काशी भुटिया (2) जोगीनाथ भुटिया और (3) चन्द्रा भुटिया दोनों फूरी भुटिया के पुत्र हैं, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.60 एकड़ या 0.24 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अगकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79—सी० एल० (7)]

S.O. 1736.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Akram Bhutia son of Kashi Bhutia (2) Joginath Bhutia and (3) Chandra Bhutia both sons of Furi Bhutia, of village Balanda the persons interested have under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.60 acres or 0.24 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (7)]

का० आ० 1737.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, (1) पुन्ना चन्द्रागर नायक सुपुत्र किकागर नायक (2) मंत्रीगर नायक (3) सनातनगर नायक, दोनों नीलागर नायक के पुत्र हैं, (4) उदयगर नायक सुपुत्र श्यामगर नायक (5) मुस्मात गुजी, गौतमगर नायक की पत्नी, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.55 एकड़ या 0.22 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अगकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है, जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79—सी०एल० (8)]

S.O. 1737.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuraing 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Purna Chandragar Nayak son of Kikagar Nayak (2) Mantrigar Nayak (3) Sanatanagar Nayak both sons of Nilagar Nayak (4) Udaygar Nayak son of Shyamgar Nayak (5) Most. Guji wife of Gautamgar Nayak of village Laxmanpur, the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.55 acres or 0.22 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19 (5)/79-CL (8)]

का० आ० 1738.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, सोम नाथ बेहरा सुपुत्र हरी बेहरा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.20 एकड़ या 0.09 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० (9)]

S.O. 1738.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Som Nath Behra son of Hari Behra of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.20 acres or 0.09 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(9)]

का० आ० 1739.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, (1) हादी नायक (2) लोक नाथ नायक (3) कपिला नायक, सभी गौरंग नायक के पुत्र हैं, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.89 एकड़ या 0.36 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० (10)]

S.O. 1739.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Hadi Nayak (2) Loknath Nayak (3) Kapila Nayak all sons of Gaurang Nayak. of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.89 acres or 0.36 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (10)]

का० आ० 1740.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा) , में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात् (1) सुकरू नायक और (2) कुलमनि नायक, दोनों चन्द्र नायक के पुत्र हैं, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.63 एकड़ या 0.25 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा) , गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० (11)]

S.O. 1740.—Whereas in persuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Sukru Naik and (2) Kulmani Nayak both sons of Chandra Naik. of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.63 acres or 0.25 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (11)]

का० आ० 1741.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, (1) कुदुरू गडानायक (2) त्रिपुरा गडानायक, दोनों सुरेन्द्रगर गडा नायक के पुत्र हैं, (3) निर्मल नायक सुपुत्र सदाई नायक (4) कला देवी, गति गाड नायक की पत्नी, (5) अमीर चन्द्र गडानायक सुपुत्र गतिगडानायक, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.51 एकड़ या 0.20 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19 (5)/ 79-सी० एल० (12)]

S.O. 1741.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Kunduru Gadanaik (2) Tripura Gada Naik both sons of Surendragar gada Naik (3) Nirmal Naik all sons of Sadai Naik (4) Kala Devi w/o Gatigad Naik (5) Amir Chandra Gadanaik S/o Gatigad Naik of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.51 acres or 0.20 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (12)]

का० आ० 1742.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा) में 45 35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम अनंताबेवेनी से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात् (1) धरमू भुक्ता (2) भागीरथी भुक्ता (3) भीमसेन भुक्ता (4) जनबेश्वर भुक्ता, सभी सरमानों भुक्ता के पुत्र हैं,

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.58 एकड़ या 0.23 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19 (5)/79-सी० एल० (13)]

S.O. 1742.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Dharmu Bhukta (2) Bhagirathi Bhukta (3) Bhimsen Bhukta (4) Janbeswar Bhukta all sons of Sarsano Bhukta of village Anantabeven the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.58 acres or 0.23 hectares which forms part of the said acquition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (13)]

का० आ० 1743.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, पूरन चन्द्र नायक सुपुत्र बिका गड नायक ,

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.60 एकड़ या 0.24 हेक्टेयर वाले, क्षेत्र जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा) गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० (14)]

S.O. 1743.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Puran Chandra Nayak s/o Bika gad Nayak of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent, authority for payment of compensation for an area of 0.60 acres or 0.24 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (14)]

का० आ० 1774.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा) में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात्, गुजी बेवा, गौतम गडा नायक की पत्नी,

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.54 एकड़ या 0.22 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकती है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा) गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19 (5) /79-सी० एल० (15)]

S.O. 1744.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Guji Bewa w/o Gautamgada Naik of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payament of compensation for an area of 0.54 acres or 0.22 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (15)]

का० आ० 1745.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा) में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात् गोबर्द्धन प्र धान सुपुत्र अंप्रति प्रधान,

ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.09 एकड़ या 0.04 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19 (5)/ 79-सी० एल० (16)]

S.O. 1745.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa) ;

And whereas (1) Gobardhan Pradhan s/o Aprati Pradhan of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.09 acres or 0.04 hectares which forms part of the said acquisition ;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL (16)]

का० आ० 1746.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा) में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात् पंचू नायक सुपुत्र बैरागी नायक, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.02 एकड़ या 0.01 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19 (5) / 79-सी० एल० (17)]

S.O. 1746.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa);

And Whereas (1) Panchu Naik s/o Bairagi Naik of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.02 acres or 0.01 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(17)]

का० आ० 1747.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों, अर्थात् (1) गोबर्द्धन प्रधान (2) भागीरथी प्रधान (3) मुखराज प्रधान, सभी अप्रति प्रधान के पुत्र हैं, (4) नरहानी नायक सुपुत्र चीना नायक (5) गौरान नायक सुपुत्र बिठल नायक (6) पति नायक सुपुत्र मकरंद नायक (7) दुबेश्वर गाड नायक (8) देवराज गाड नायक (9) खगेश्वर गाड नायक, सभी सुरेन्द्र नायक के पुत्र हैं, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.79 एकड़ या 0.32 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण धेनकानल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें धेनकानल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19 (5)/79-सी० एल० (18)]

S.O. 1747.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa);

And whereas (1) Gobardhan Pradhan (2) Bhagirathi Pradhan (3) Mukhraj Pradhan all sons of Aprati Pradhan (4) Narhani Naik S/o China Nayak (5) Gauran Naik S/o Bithal Naik (6) Pati Naik S/o Makarand Naik (7) Dubesh-warged Naik (8) Devrajgod Naik (9) Khageshwargad Naik all sons of Surendar Naik of village Laxmanpur, the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.79 acres or 0.32 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(18)]

का० आ० 1748.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) द्वारा जारी की गई अधिसूचना सं० का० आ० 3166, तारीख 26 अगस्त, 1972 के अनुसरण में, ग्राम भरतपुर और लक्ष्मणपुर, थाना तालचेर कोलियरी, जिला धेनकानल (उड़ीसा), में 45.35 एकड़ (लगभग) या 18.37 हेक्टेयर (लगभग) माप वाली भूमि अर्जित कर ली है ;

और ग्राम लक्ष्मणपुर से हितबद्ध व्यक्तियों,अर्थात् नरहानी नायक सुपुत्र बागा नायक, ने उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन 0.70 एकड़ या 0.28 हेक्टेयर वाले क्षेत्र, जो उक्त अर्जन का भागरूप है, के लिए प्रतिकर के संदाय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दावा किया है ;

और उक्त अर्जन के लिए संदेय प्रतिकर की रकम सहमति द्वारा नियत नहीं की जा सकी है और प्रतिकर की प्रस्तावित रकम की पर्याप्तता के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त हितबद्ध व्यक्तियों को संदेय प्रतिकर की रकम अवधारित करने के प्रयोजन के लिए एक अंशकालिक अधिकरण ढेंकानाल (उड़ीसा), गठित करती है जिसमें ढेंकानाल का जिला न्यायाधीश होगा ।

[संख्या 19(5)/79-सी० एल० (19)]
एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O. 1748.—Whereas in pursuance of the notification of the Government of India in the late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S. O. 3166 dated the 26th August, 1972, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government has acquired the lands measuring 45.35 (approximately) or 18.37 hectares (approximately) in villages Bharatpur and Lachhmanpur Thana Talcher Colliery, District Dhankanal (Orissa);

And whereas (1) Narhani Naik s/o Bana Naik of village Laxmanpur the persons interested have, under section 13 of the said Act, preferred the claim to the competent authority for payment of compensation for an area of 0.70 acres or 0.28 hectares which forms part of the said acquisition;

And whereas the amount of compensation payable for the said acquisition could not be fixed by agreement, there being a dispute as to the sufficiency of the amount of compensation offered;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of the District Judge for the purpose of determining the amount of compensation payable to the aforesaid persons interested.

[No. 19(5)/79-CL(19)]
S. R. A. RIZVI, Director.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1979

का०आ० 1749.—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में इस्पात और खान मंत्रालय, खान विभाग के अधीन निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उक्त उपनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करती है :

1. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय, जयपुर ।

[सं० ई०-11017/5/78-हिन्दी]
मालती सुनीता सिन्हा, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 7th May, 1979

S.O. 1749.—In pursuance of Sub-rule (4) of rule 10 of the official Languages (use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following office under the Ministry of Steel and Mines, Department of Mines, the staff whereof have acquired working Knowledge of Hindi, for the purposes of the said sub-rule :—

1. Western Regional office of Geological Survey of India, Jaipur.

[No. E11017(5)/78-Hindi]
M. S. SINHA, Dy. Secy.

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1979

का०आ० 1750.—केन्द्रीय सरकार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1976 (1976 का 89) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय के अधीक्षक श्रीमती अमिया गोस्वामी को 23 अप्रैल, 1979 से सहायक संदाय आयुक्त नियुक्त करती है । उनकी नियुक्ति श्री हरी मोहन दास के स्थान पर की गई है जिनको लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

[मि० सं० 8(108)/76 के० आई०]
टी० वी० नायर, उप-सचिव,

(Department of Steel)

New Delhi, the 14th May, 1979

S. O. 1750.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Act, 1976 (89 of 1976), the Central Government hereby appoints with effect from 23rd April, 1979 (forenoon) Shrimati Amiya Goswami, Superintendent in the Office of the Iran and Steel Controller, Calcutta, as Assistant Commissioner of Payments in place of Shri Hari Mohan Das transferred to the Office of the Iron & Steel Controller.

[File No. 8(108)/76-K.I]
T. V. NAYAR, Dy. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

(शुद्धि पत्र)

नई दिल्ली, 1 मई, 1979

का०आ० 1751.—श्री ए० भार, तकनीकी अधिकारी के बारे में इस विभाग के दिनांक 6 मार्च, 1973 के शुद्धि-पत्र संख्या 52/21/68-आर० ई० 1 को रद्द किया जाता है ।

[सं० 52/15/74-एफ० सी० III (वाल्यूम-III)]
बख्शी राम, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st May, 1979

S.O. 1751.—This Department Corrigendum No. 52/21/68-RE. I dated the 6th March, 1973, in respect of Shri A. Bhar, Technical Officer is cancelled.

[No. 52/15/74-FC. III (Vol. III)]
BAKHSHI RAM, Dy. Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 1979

का०आ० 1752.—श्री आर० बी० सिंह, निरीक्षक, वन्य-प्राणि क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली को अधिनियम की उक्त धारा की उप-धारा (2) तथा (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर वन्य-प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 50 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है ।

[सं० 2-10/79-एफ० आर० वाई० (डब्ल्यू० एल०)]
एन० डी० जयाल, निदेशक, वन्यप्राणि संरक्षण

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 8th May, 1979

S.O. 1752.—Shri R. V. Singh, Inspector, Wildlife Regional Office, New Delhi is hereby authorised to exercise powers under Section 50 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, except the powers provided under sub-sections (2) and (6) of the said Section of the Act.

[No. 2-10/79-FRY(WL)]

N. D. JAYAL, Director, Wildlife Preservation

पेट्रोलियम, रासायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1979

का०आ० 1753.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3604 तारीख 29-11-78 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पाइप लाइन डी० एस० 23 से जी० सी० एस० तक बिछाने के लिये

राज्य-गुजरात जिला—खेड़ा तालुका—खेभात

गांव	सर्वेक्षण	हेक्टेयर	एआर ई सेन्टीयर
1	2	3	4	5
झालापुर	कार्ट ट्रेक	0	00	49
	181	0	07	84
	182	0	00	70
	179	0	07	84
	178	0	05	60
	180	0	00	84
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
नेजा	206	0	00	63
	205	0	08	40
	204	0	07	70
	200	0	11	90
	198	0	00	70
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
लांबड़ा	99	0	02	10
	114	0	01	40
	113	0	02	10
	112	0	02	80
	102	0	07	35
	103	0	07	70
	108/2	0	03	50
	108/1	0	04	20
	107	0	03	15
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
	24	0	05	95
	19/1	0	06	30
	11	0	25	20
	20/1	0	01	40
	कार्ट ट्रेक	0	00	49
पालडी	36	0	09	10
	34	0	16	10

[सं० 12016/13/78-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 30th April, 1979

S.O. 1753.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. No. 3604 dated 29-11-78 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Subsection (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of the declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from D.S. 23 to G.C.S.

State : Gujarat Distt : Kaira Taluka—Cambay

Village	Survey No	Heat	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Zalapur	Cart-track	0	00	49
	181	0	07	84
	182	0	00	70
	179	0	07	84
	178	0	05	60
	180	0	00	84
	Cart track	0	00	49

1	2	3	4	5
Noja	206	0	00	63
	205	0	08	40
	204	0	07	70
	200	0	11	90
	198	0	00	70
	Cart track	0	00	49
Sotehada	99	0	02	10
	114	0	01	40
	113	0	02	10
	112	0	02	80
	102	0	07	35
	103	0	07	70
	108/2	0	03	50
	108/1	0	04	20
	107	0	03	15
	Cart track	0	00	49
	24	0	05	95
	19/1	0	06	30
	11	0	25	20
	20/1	0	01	40
	Cart track	0	00	49
Palsi	36	0	09	10
	34	0	16	10

[No. 12016/13/78-Prod.]

का० आ० 1754.--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3636 तारीख 23-12-1978 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन आयल कारपोरेशन लि० सभी संबंधों से बाधाओं से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तहसील : रायपुर	जिला:पाली	राज्य: राजस्थान		
ग्राम	खसरा नं०	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	ऐयर	वर्गमीटर
रायपुर	2308/1	0	07	29
दीपावास	332	0	08	10
मेगदड़ा	73	0	05	12
माकड़वाली	80	0	00	81
फताखेड़ा	42/94	0	12	44
	39/93	0	08	10
सैंदड़ा	658	0	00	14
	685	0	00	81
सबलपुरा 11	218	0	00	60
	373	0	00	18
सराधना	181	0	03	10

[सं० 12020/8/78-प्रो०]

नरेन्द्र सिंह, सक्षम प्राधिकारी

कम्पीटेन्ट अथोरिटी, राजस्थान स्टेट

S.O. 1754.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer (Department of Petroleum) S. O. 3636 dated 23-12-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the scheduled appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Tehsil : Raipur	District : Pali	State : Rajasthan		
Village	Khasra No.	Area		
		H.	A.	Sq. M.
Raipur	2308/1	0	07	29
Deepawas	332	0	08	10
Megdara	73	0	05	12
Makarwali	80	0	00	81
Fata Khera	42/94	0	12	44
	39/93	0	08	10
Sendra	658	0	00	14
	685	0	00	81
Sabalpura II	218	0	00	60
	373	0	00	18
Saradhna	181	0	03	10

[No. 12020/8/78-Prod.]

NARENDRA SIGHN, Competent Authority,
Rajasthan State

शुद्धिपत्र

का० आ० 1755---भारत सरकार के राजपत्र, भाग---II, खंड-3, उपखण्ड (2) दिनांक 9 सितम्बर 1978 के पृष्ठ संख्या 2404 पर का० आ० संख्या 2607 के अन्तर्गत प्रकाशित भारत, सरकार पेट्रोलियम

की अधिसूचना संख्या 120/6/6/78-Prod.-3 दिनांक 16 अगस्त 1978 के अधीन निम्नलिखित अनुसूची के स्थान पर नीचे दी गई अनुसूची को पढ़े :

पढ़े			के लिये		
गाँव	तालुक	जिला	गाँव	तालुक	जिला
बालसासाण	विरमगाम	अहमदाबाद	बालसासण	विरमगाम	अहमदाबाद
सर्वेक्षण	हेक्टेयर एआरई सेंटीयर		सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर एआरई सेन्टीयर	
336/3	0–01–68		336/3	0–01–68	

[सं० 12016/6/78 प्रो०]

ERRATUM

S.O. 1755.—In the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum No. 12016/6/78-Prod-III dated 16th August, 1978, under S.O. No. 2607 in the Gazette of Government of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 9th September, 1978, Page No. 2404.

Read				For			
Village	Taluka	District		Village	Taluka		District
Balsasan	Viramgam	Ahmedabad		Balsasan	Viramgam		Ahmedabad
Survey No.	Hectare	Are	Centiare	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
366/3	0	01	68	336/3	0	01	68

[No. 12016/6/78-Prod]

नई दिल्ली 1 मई, 1979

का० आ० 1756.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20-2-1978 की का० आ० संख्या 112 (क) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना के साथ लगी सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का अपना आशय घोषित किया था।

और यत: सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

और अब यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस अधिसूचना के साथ लगी सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का निर्णय किया है,

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा इस अधिसूचना के साथ लगी सूचियों में विनिर्दिष्ट पाइप लाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार घोषित करती है,

और यह भी कि उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित रहने के स्थान पर इस घोषणा के प्रकाशन की तिथि से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई-400020 में निहित रहेंगे जो भारमुक्त होंगे।

(कार्य सूची)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी (माहुल) से सान्ताक्रुज हवाईअड्डे तक पाइपलाइन राज्य महाराष्ट्र जिला : बम्बई

गाँव/उपनगर	सर्वे	हेक्टर	आर	सेंटेरिया
अनिक	माहुल गाँव तक सड़क	0	0	22
	36 (बीपीसीएल)	0	3	58
	रेलवे गलियारा (कारीडोर)	0	3	02
मारावली	रेलवे गलियारा	0	1	84
	101	0	8	10
चेम्बूर	127 खेल	0	0	44
	रेलवे गलियारा	0	18	60
	ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (सड़क)	0	0	63
कुरला	रेलवे गलियारा	0	11	00
	तनसा वाटर पाइपलाईन वे	0	6	37
	कुरला स्टेशन रोड	0	0	16
	तनसा वाटर पाइपलाइन वे	0	2	70
	कामगर नगर को सड़क	0	0	06
	विहार वाटर पाइपलाइन वे	0	2	66
	कुरला डेयरी को सड़क	0	0	42
	पुलिस कालोनी को सड़क	0	3	82
	रेलवे कारीडोर	0	6	47
	विहार वाटर पाइपलाइन वे	0	9	52
	लायो पुल रोड	0	0	09
	विहार वाटर पाइपलाइन वे	0	5	67
	पक्की सड़क	0	0	09
	विहार वाटर पाइपलाइन वे	0	3	46
	लाल बहादुर शास्त्री मार्ग (बम्बई-आगरा रोड)	0	0	20
	विहार वाटर पाइपलाइन वे	0	14	02
	बेल बाजार–कमानी रोड	0	0	10
	विहार वाटर पाइपलाइन वे (कुजवाड़ा मार्ग)	0	4	02
	हवाई अड्डे का क्षेत्र	0	9	10
	पक्की सड़क	0	0	09
	विहार वाटर पाइपलाइन वे (कजुवाड़ा मार्ग)	0	5	39
	पक्की सड़क	0	0	11
	विहार वाटर पाइपलाइन वे (कजुपाड़ा मार्ग)	0	9	06
मारोल	अंधेरी-कुरला मार्ग (माथुरदास वसनजी मार्ग)	0	13	68
	एयरपोर्ट एरिया	0	3	93
साहर	एयरपोर्ट एरिया	0	7	82
सान्ताक्रूज	एयरपोर्ट एरिया	0	45	60

ध्यान दें: 1. एम सी जी बी वाटर पाइपलाइन वे/सड़क के बारे में मालगुजारी/शहरी सर्वे नक्शों में कोई सर्वे नम्बर नहीं है।

2. हवाई अड्डे क्षेत्र में दिखाई गई पाइपलाइन पंक्ति विद्यमान मालगुजारी नक्शों के कई सर्वे नम्बरों से गुजरेगी। ये मार्गाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण के पास है अत: मार्ग अर्जन अधिकार केवल हवाईअड्डा क्षेत्र में होना दिखाया गया है।

[सं० 12017/1/79–प्रो०)]

एस० एम० आई० नदीम, अवर सचिव

New Delhi, the 1st May, 1979

S.O. 1756.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 112(E) dated 20-2-1978 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1972 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corpn. Ltd., Bombay 400020, free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from H P. Refinery (Mahul) to Santacruz Airport

State : Maharashtra District : Bombay Bombay City.

Village/ Suburb	Survey Number	Hec-tare	Are	Cen-taire
1	2	3	4	5
Anik	Road to Mahul Village	0	0	22
	36 (BPCL)	0	3	58
	Railway Corridor	0	3	02
Maravli	Railway Corridor	0	1	84
	101	0	8	10
Chembur	127 Area	0	0	44
	Railway Corridor	0	18	60
	Eastern Express Highway (Road)	0	0	63
Kurla	Railway Corridor	0	11	00
	Tansa Water Pipeline Bay	0	6	37
	Kurla Station Road	0	0	16
	Tansa Water Pipeline Bay	0	2	70
	Road to Kamgar Nagar	0	0	06
	Vihar Water Pipeline Bay	0	2	66
	Road to Kurla Dairy	0	0	42
	Road to Police Colony	0	3	82
	Railway Corridor	0	6	47
	Vihar Water Pipeline Bay	0	9	52
	Leo Pull Road	0	0	09
	Vihar Water Pipeline Bay	0	5	67
	Metalled Road	0	0	09
	Vihar Water Pipeline Bay	0	3	46
	Lal Bahadur Shastri Marg (Bombay-Agra Road)	0	0	20
	Vihar Water Pipeline Bay	0	1	02
	Ball Bazar-Kamani Road	0	0	10
	Vihar Water Pipeline Bay (Kajupada Marg)	0	4	02
	Airpot Area	0	9	10
	Matalled Road	0	0	09
	Vihar Water Pipeline Bay (Kajupada Marg)	0	5	39
	Metalled Road	0	0	11
	Vihar Water Pipeline Bay (Kajupada Marg)	0	9	06
Marol	Andheri-Kurla Road (Mathurdas Vasanji Marg)	0	13	68
	Airport Area	0	3	93
Sahar	Airport Area	0	7	82
Santa Cruz	Airport Area	0	45	50

Notes :

1. The cadestral/ city survey maps do not contain any survey numbers for the MCGB Water Pipeline Bay/Roads.

2. Pipeline alignment shown to be in the Airport area, shall be passing through many survey numbers on the existing cadesral maps. However, these are to be with International Airports Authority and so the right- of-way acquisition is shown only to be in Airport area.

[No. 12017/1/78-Prod.]
S.M.Y. NADEEM, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 मई, 1979

का० आ० 1757—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 111 के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने कुल्लू टेलिफोन केन्द्र में दिनांक 16-6-79 से प्रमापित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-8/79 पी एच बी)]
आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक (पी० एच बी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 17th May, 1979

S.O. 1757.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 16-6-1979 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kulu Telephone Exchange, N.W. Circle.

No. 5-8-/79-PHB.]]
R. C. KATARIA, Assistant Director General (PHB)

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1979

का० आ० 1758.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक

औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अग्निशमन सेवा विभाग में ड्राइवरों, लीडिंग फायरमैन और फायरमैन के संबंध में काम के घंटे प्रतिदिन 12 घंटों से कम कर 8 घंटे करके, क्या प्रबंधतंत्र का ऐसे श्रमिकों को 25 प्रतिशत प्रतिकर की अदायगी को बन्द करना न्यायोचित है यदि हाँ, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष, यदि कोई हो, के हकदार है ?

[सं०-एल-35015/3/78-डी० 4 (ए)]
नन्द लाल, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 25th April, 1979

S.O. 1758.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Cochin Port Trust, Cochin and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether with the reduction of working hours from 12 hours to 8 hours per day in respect of Drivers, Leading Firemen and Firemen in the Fire Service Department of Cochin Port Trust, the management are justified in discontinuing payment of 25 per cent compensation to such workers? If so, what relief if any, are the workers concerned entitled to?

[No. L-35015(3)/78-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

New Delhi, the 8th May, 1979

S.O. 1759.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by Shri Shamrathi Miner, Jamadoba Colliery, Ex-C.R.O. Camp No. 16, Labour Coloney Jamadoba, Post Office Jamadoba, District Dhanbad, which was received by the Central Government on the 4th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri J. P. Singh, Presiding Officer

Complaint No. 4 of 1976

In the matter of a complaint under section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 47) in the matter of a reference No. 21 of 1974.

PARTIES :

Shri Shamrathi Miner,
Jamadoba colliery, Ex-C.R.O. camp,
No. 16 Labour Coloney Jamadoba,
P. O. Jamadoba, Dist : Dhanbad. ...Complainant.

Vs

M/S Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
Jamadoba, P.O : Jamadoba,
Dist : Dhanbad. ...Opp. Party.

APPEARANCES :

On behalf of the complainant Shri B. N. Sharma, Vice President, Janata Mazdoor Sangh.
On behalf of the Opp. Party . None.
State : Bihar. . . . Industry : Coal.

AWARD

Dhanbad, 30th April, 1979.

This is a complaint filed under section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 by Shri Shamrathi Miner complaining that the opposite party has contravened the provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 in suspending him for 10 days w.e.f. 30.8.76. The case proceeded along its course. Ultimately when the case was fixed for hearing on 30.3.79, Shri B. N. Sharma appeared for the complainant and submitted that the complainant was on longer interested to press his complaint. Accordingly, the complaint petition is dismissed as not pressed.

J. P. Singh, Presiding Officer.

[No. L-20025(18)/79-D. III(A)]

New Delhi, the 9th May, 1979

S.O. 1760.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in respect of a complaint under Section 33A of the said Act filed by Shri Jitendra Pal Singh, Electrician, Chasnala Colliery, Post Office Patherdih, District Dhanbad, which was received by the Central Government on the 4th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT :

Shri J. P. Singh, Presiding Officer.

Complaint No. 8 of 1975

In the matter of a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 1947) arising out of Reference No. 43 of 1975.

PARTIES :

Shri Jitendra Pal Singh,
Electrician,
Chasnala Colliery. ...Complainant.

Versus

Indian Iron and Steel Co. Ltd.,
Chasnala Colliery,
P.O. Patherdih,
Distt. Dhanbad. ..Opp. Party.

APPEARANCES :

One behalf of the complainant.—None.

On behalf of the Opposite Party—Shri T. P. Chowdhury Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

AWARD

Dhanbad, 30th April, 1979

This is a complaint filed under section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 by Shri Jitendra Pal Singh, Electrician complaining that the opposite party has contravened the provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 in suspending him for more than 10 days w.e.f. 22-9-1975. Notices were issued and both parties filed their appearances. Ultimately when the case was fixed for hearing on 31-3-1979, Shri T. P. Choudhury, the learned Advocate for the opposite party appeared and submitted that the matter has been amicably settled. Later on Shri B. N. Sharma appeared for the complainant and made the same submission and further submitted that the complainant was no longer interested to press his complaint. Accordingly, the complaint petition is dismissed as not pressed.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20025(18)/79-D.III(A)(i)]

S.O. 1761.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Md. Sallahuddin, Mechanical Fitter/Operator, Main Ropeway Station A of Chasnala Colliery, Post Office Patherdih, District Dhanbad, which was received by the Central Government on the 4th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT

Shri J. P. Singh, Presiding Officer.

Complaint No. 1 of 1976

In the matter of a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 47) arising out of Reference No. 43 of 1975.

PARTIES :

Md. Sallahuddin, Mechanical Fitter/Operator, Main Ropeway Station A of Chasnala Colliery.

...Complainant.

Versus

The Indian Iron and Steel Co. Ltd., Chasnala Colliery, P.O. Patherdih, Distt. Dhanbad. ...Opp. Party

APPEARANCES :

On behalf of the complainant.—None.

On behalf of the Opp. Party.—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

AWARD

Dhanbad, the 30th April, 1979

This is a complaint filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 by Md. Sallahuddin, Mechanical fitter/operator complaining that the opposite party has contravened the provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 by making prejudicial changes in the condition of his services. The case proceeded along its course. Neither the complainant nor his authorised representative appeared before the court on several dates. Even on 31-3-1979 when the case was fixed for hearing the complainant did not turn up. It therefore appears that the complainant was no longer interested to press his complaint. Accordingly, the complaint petition is dismissed as not pressed.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20025(18)/79-D.III(A)(2)]

S. H. S. IYER, Desk Officer.

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का० आ० 1762.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट के बारे में नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली की सर्वश्री के० एस० रंगानाथन और असन मोहीदीन को क्रमशः 17 अगस्त, 1978 और 14 फरवरी, 1978 से रिवार्ट करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं।

[सं० एल०-23012/3/78-डी०-4 (बी)]

शशि भूषण, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1762.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli in reverting Sarva Shri K. S. Ranganathan, and Asan Mohideen on 17th August, 1978 and the 14th February, 1978, respectively, is justified. If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

[F. No. L-23012(3)/78-D. IV(B)]

S.O. 1763.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between the management of Stores Department of Satgram Area of Eastern Coalfields Ltd. and their workmen which was received by the Central Government on the 8th May, 1979.

IN THE MATTER OF ARBITRATION UNDER SECTION 10A OF INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 WITH REGARD TO THE INDUSTRIAL DISPUTE OVER FIXATION OF GRADE/CADRE IN RESPECT OF SHRI N. K. SINGH OF STORES DEPARTMENT OF SATGRAM AREA OF EASTERN COALFIELDS LTD., BETWEEN THE MANAGEMENT OF SATGRAM AREA OF EASTERN COALFIELDS LTD. AND THE WORKMAN REPRESENTED BY KOYLA MOZDOOR CONGRESS (HMS).

PRESENT :

Shri D. V. Ramachandran, Regional Labour Commissioner (Central) and Arbitrator under section 10A of I.D. Act 1947.

Representing workman—Shri S. K. Pandey, Secretary, Koyla Mazdoor Congress, Gorai Mansion, G.T. Road, Asansol. Shri N. K. Singh, the workman concerned.

Representing the Employer—(1) Shri N. Das, Advocate, (2) Shri Amitava Sinha, Assistant Chief Personnel Officer, Satgram Area of Eastern Coalfields Ltd., P.O. Devchandnagar, District Burdwan (W.B.)

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mining.
No. 1(3)/78-B. 3 Dated, Asansol, the 28th April, 1979.

AWARD

The management of Satgram Area Store under Satgram Area of Eastern Coalfields Ltd., and their workmen represented by Koyla Mazdoor Congress (HMS), Gorai Mansion, G. T. Road, Asansol, referred the following dispute to my arbitration under Section 10A of Industrial Disputes Act, 1947, by an agreement signed between them on 17th November, 1978 which was published in the Gazette of India in Part-II Section 3 Sub-section (ii) dated 30th December, 1978 (Gazette No. 52-P. 3511-S.O. 3753) :—

"Whether the action of the management of Satgram Area Store under Satgram Area of M/s. Eastern Coalfields Ltd., is justified in fixing with effect from August, 1973 Shri N. K. Singh, Store Superintendent of Technical 'A' to the Grade of Store Keeper and putting in Special Grade in terms scale of pay as per wage Board Recommendations for coal mining industry read with National Coal Wage Agreement; If not, to what relief the workmen is entitled ?"

The parties were heard on 30th January, 1979, 7th February, 1979, 20th February, 1979, 3rd March, 1979, 15th March, 1979 and finally on 2nd April, 1979. The management produced records pertaining to manpower, 'Form B' Register, including report of screening committee, pay sheets/register of wages for the period from January, 1972 to December, 1973 which were taken as evidence. Shri R. P. Singh, Manager, Khas Chalbalpur Colliery and Shri N. K. Singh, the workman concerned, were examined as witnesses on behalf of the workmen. The management did not produce any witness.

It is admitted that at the time of take over, Shri N. K. Singh, the workman concerned, was working as Store Superintendent in technical and supervisory grade 'A'. The contention of the management as given in the written statement signed by the General Manager, Satgram Area is as follows :—

"That after nationalisation of the said coal mine it appeared to the management that although Shri N. K. Singh was performing clerical duties and had no connection with performance of any technical and supervisory job there must have been same inconsistency in his designation and grade shown in the records of the said colliery as Stores Superintendent in Technical 'A'.

That it was further found that the said Chalbalpur Colliery was a small colliery and there were only 400 employees in the roll of the said colliery and there was no justification for keeping any Stores Superintendent for looking after the work of colliery store and neither Shri N. K. Singh had any qualification for being designated and graded as such and the whole thing left room for suspicion that there was some fraud or manipulation in the matter ;

That a probe into the matter was made and on the face of said glaring inconsistency the management could not rely about the genuineness of the designation and grade shown in the case of Shri N. K. Singh and for avoiding all anomalies Shri Singh was designated as Store Keeper and he was placed in Special Grade as per Wage Board recommendation and his pay was protected and he also got usual increments in the subsequent years.

That the management's aforesaid action was fully justified and the management has got no obligation to honour absurd and inconsistent designations and grades if found any by the erstwhile management having no consistency with nature of work performed by the workman and having no competence for being designated as such ;

That Section 14 of the Coal Mines Nationalisation Act enjoins continuation of the existing terms and conditions of service of the workman but does not enjoin for continuing absurd and inconsistent terms."

It is clear from the above that the management has taken unilateral action to change the service conditions of the workman, which is against the provisions of Section 14 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973. If at all service conditions had to be changed, they have to be changed in accordance with due procedure, which implied that the workman should be given opportunity to accept the new terms of service conditions and scales of pay. The management cannot unilaterally come to conclusion that the erstwhile management had absurd and inconsistent terms. They cannot also come to any conclusion that there was fraud or manipulation in the matter without proper enquiry. If at all there was any such probe, it is clear from the evidence that Shri Singh, the workman, was not given any opportunity to place his view points in the matter before the management. Moreover, Management did not produce any such enquiry/probe papers. During the proceedings the management has not been able to elicit information or produce any evidence in support of their written statements and arguments.

It is seen from the 'Form B' Register of Khas Chalbalpur Colliery that Shri N. K. Singh was designated as Store Keeper and his date of appointment has been shown as 4th January, 1964 and thereafter was duly promoted by the Agent as 'Store Superintendent' w.e.f. 1st September, 1971 in the Grade 'A' technical and supervisory (Rs. 405-20-605-25-730 of Central Wage Board Recommendations). It is also seen that Shri Ram Pratap Singh who was Manager of Khas Chalbalpur Colliery from 1st November, 1970 had recommended his case for promotion of Shri N. K. Singh to the Agent and also has given a certificate that Shri Singh was managing purchasing of materials control and store keeping. In his deposition Shri R. P. Singh has stated that all the stores of Pure Searsole Colliery was, also, being looked after from Khas Chalbalpur Colliery including purchase of medicines, coal tub repairing and maintenance of vehicles. The workman in his deposition has stated that he was independently in charge of all store functioning, purchase of vehicles of Khas Chalbalpur Colliery as well as Pure Searsole Colliery. The raising of the colliery was stated to be about 16000 tonnes approximately at that time. Shri N. K. Singh is also a Graduate from Gorakhpur University (1959). After the take-over of the colliery, the workman's pay only was protected and he was put in the special grade clerical (Rs. 305-15-425-20-505) without giving him any opportunity for which the workman was continuously making representations. It is seen from the pay sheet of December, 1972 of Khas Chalbalpur Colliery that Shri N. K. Singh has been shown as Stores Superintendent and paid basic salary of Rs. 445. Earlier pay sheets from January 1972 to November, 1972 also show his designation as Stores Superintendent. Pay sheet of June, 1973 also shows designation as 'Stores Superintendent'. It is only from the month of September, 1973 no designation has been shown against the name of Shri Singh but his basic salary was shown as Rs. 465. The same position is seen even in the pay sheet of January, 1974 which was produced before me. This shows that the management was having second thought about the designation to be given to the workman, main trouble being that there was no designation of Store Superintendent in the

Wage Board Recommendations. In the Screening Committee list submitted to the Coal Mines Authority by the Manager, Khas Chalbalpur Colliery at the time of nationalisation shows designation and work of Shri Singh as Stores Superintendent.

From the above records and evidences it is clear that at the time of nationalisation Shri N. K. Singh was enjoying the status of Stores Superintendent and was in supervisory and technical Grade 'A' (i.e. Rs. 405—730). It was for the management to protect his scale and give suitable designation to him after nationalisation instead of reducing his status and fitting him in any other scale of pay where the pay drawn by him could be fitted in. It may be seen for clerical special grade as well as technical and supervisory Grade 'A' the middle scale is Rs. 420-20-605. Hence, it was easy for the management to give him an increment and satisfy themselves that they have protected his pay. The scales have been revised from 1st January, 1975 and hence the employee having not been given proper scale of pay, has further suffered. It is also stated that there is a vacancy of Chief Store Keeper after transfer of Shri Nagpal in the same colliery.

In view of the above, I hereby direct the management to restore to Shri N. K. Singh his original scale of pay of Rs. 405-20-605-25-730 and allow him the revised scale of pay and give him proper designation in the technical supervisory grade 'A' with effect from 1973. He should be considered as having been fixed at Rs. 455 (Rupees four hundred and forty five) in the grade of Rs. 405—730 at the time of nationalisation and granted consequential benefits. Arrears, if any, shall be paid to the said workman within a month from the date of this award.

No order as to the costs.

D. V. RAMACHANDRAN, Regional Labour Commissioner (Central) & Arbitrator under Sec. 10A of I.D. Act 1947.

[F. No. 23012(3)/78-D.IV(B)]

SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

New Delhi, the 14th May, 1979

S.O. 1764.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by Shri J. K. Singh, R.T.O., Chasnala Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Patherdih, District Dhanbad, which was received by the Central Government on the 5th May, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT

Shri J. P. Singh, Presiding Officer.

Complaint No. 3 of 1976

In the matter of a complaint under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 (XIV of 47) arising out of Reference No. 43 of 1975.

PARTIES :

Shri J. K. Singh,
R.T.O.,
Chasnala Colliery of
M/s. Indian Iron & Steel Co. Ltd. ...Complainant.

Versus

The Indian Iron & Steel Co. Ltd's
Chasnala Colliery, P.O. Patherdih,
Distt. Dhanbad. ...Opp. Party.

APPEARANCES :

On behalf of the Opp. Party : Shri P. K. Bhandari, Personnel Officer.

On behalf of the Complainant.—None.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 30th April, 1979

AWARD

This is a complaint filed under Section 33A of the Industrial Disputes Act, 1947 by Shri J. K. Singh, R.T.O. complaining that the opposite party has contravened the provisions of Section 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 in transferring him to Chiria Ore Mines on and from 1st August, 1976. The case proceeded along its course. Neither the complainant nor his authorised representative appeared before the court on several dates. Ultimately, when the case was fixed for hearing on 31-3-1979, Shri P. K. Bhandari appeared for the opposite party and none appeared for the complainant. It appears that the complainant was no longer interested to press his complaint. Accordingly, the complaint petition is dismissed as not pressed.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

New Delhi, the 15th May, 1979

S.O. 1765.—In pursuance of Section 17 of the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Korea Colliery of Western Coalfields Limited District Surguja, Madhya Pradesh and their workmen, which was received by the Central Government on 3rd May, 1979.

BEFORE SHRI S. N. JOHRI, B.Sc., LL.M., PRESIDING OFFICER

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR, (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(30) of 1978

PARTIES :

Employers in relation to the management of Korea Colliery of Western Coalfields Limited, Distt. Surguja (M.P.) and their workman represented through the President Surguja Coal Workers Union (AITUC), P.O. Korea Colliery, Distt. Surguja (M.P.).

APPEARNCES :

For Workman—Shri P.K. Thakur, Advocate.

For Management—Shri P.S. Nair, Advocate

INDUSTRY : Coal. DISTRICT : Surguja (M.P.)

AWARD

Dated : April 25, 1979.

This is a reference made by the Government of India, in the Ministry of Labour vide it's order No. L-22012(21)/77-D-IV(B), of 3rd June, 1978, for the adjudication of the following industrial dispute ;

"Whether the action of the management of Korea Colliery of Western Coalfields Limited, Distt. Surguja in dismissing Shri Seiku S/o. Sukhi, Category-I Mazdoor of Korea Colliery vide order No. KR/CMA/OO/5358 dated 10th August, 1975 from service is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. It is not disputed that referring to clause 17(1)(r) of standing orders the workman was served with the following charge sheet on 14-12-1974.

"That on 12-12-74 while Shri A.S. Desai, A.L.W.O., Korea Colliery was passing through the bus-stand of Korea Colliery you abused him in filthy language and also threatened him with dire consequences."

The workman filed a reply of total denial. Domestic enquiry was held. Enquiry Officer reported that the charge was proved and thereupon, accepting the findings, the disciplinary authority ordered his dismissal vide order dated 10-8-1975 referred to in the schedule of reference.

3. The case of the Union is that the charge was vague, opportunity to produce defence was not allowed, presenting officer was a man of rival union. The management was supporting it and it in its' turn got support from the rival union. The findings were perverse and the punishment was harsh because it was grossly disproportionate to the misconduct charged.

4. Management has denied, vagueness in charge, causing of any prejudice on account of the alleged vagueness, not giving of opportunity to lead evidence in defence, perversity and disproportionately harh character of punishment.

5. Preliminary issues were framed about vagueness of the charge fairness of the proceedings and perversity of the findings.

6. Charge is perse vague because it omits to mention the abuses and the words of threat specifically. However the workman or his representative did not raise any objection about the vagueness of the charge. He made an omnibus denial. That means that he was denying the whole incident as well as the use of abusive or threatening language. The complainant A.L.W.O. was the first witness to be examined. He tried to reproduce some abusive threatening words while abstained spelling out the remaining which were too filthy to be uttered according to his own cultural notions. Still in cross examination no attempt was made to get the abusive and threatening words specifically spelt out. No specific prejudice was alleged to have been caused in defence and Enquiry cannot be vitiated unless material prejuice is shown to have been caused as is the case even in criminal cases.

7. The Union alleged that full opportunity to preduce defence witnesses was given. Management denied it. According to the management the workman avoided to participate at the defence stage even inspite of several adjournments and service of notices. The union has failed to prove its' allegation hence the point is decided against it.

8. As for perversity the evidence appears to have been broadly speaking correctly appreciated. This Tribunal did not sit in appeal and has no jurisdiction to take a different view unless that appreciation of evidence by the enquiry officer is wholly fallacious and could not be termed as a possibly justifiable view. There is thus no perversity in findings.

9. As the union appears to be in no need to participate I think opportunity being given to the union to produce evidence on the question of quantum of evidence shall be of no avail. The incident took place outside the place of work or place of duty. Union rivalry is alleged. The workman is alleged to have trespassed and is being ousted from the land occupied by him. All this is likely to create temper. The spelt out words are not very filthy in the category of workers to which the workman belongs. There is previous misconduct alleged. He has already put in 15 years of service as admitted by the learned counsel for the management.

10. The findings of guilt are thus maintained. But the punishment of dismissal awarded by the disciplinary authority being two harsh & disproportionate to the seriousness of the misconduct, is set aside.

11. The concerned workmen shall be reinstated within one month of the publication of the award, without back wages and his annual increments shall stand stopped for a period of five years without affecting future increments. He shall be deemed to have continued in service for all other purposes. The award is given accordingly. Parties shall bear their own costs.

Dated : 25-4-1979.

S. N. JOHRI, Presiding Officer

[No. L. 20025/18/79-D.III(A)(3)]

S. H. S. IYER, Desk Officer.

नई दिल्ली, 10 मई, 1979

का०आ० 1766.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2031 तारीख 29 जून 1978 के अनुक्रम में भारत हैवी प्लैट एण्ड वेसेल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 1 जुलाई 1978 से 30 जून 1979 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, की अवधि के लिए छूट देती है।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अवधि' कहा गया है) ऐसी विवरणियां , ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(1) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख का, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा किए गए उन कायदों को, जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उस कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ;

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा——

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है ; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं ; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[सं० एस-38014/41/78-एच०आई०]

हंस राज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 10th May, 1979

S.O. 1766.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2031 dated the 29th June, 1978, the Central Government hereby exempts the Bharat Heavy Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam from the operation of the said Act for a further period from the 1st July, 1978 upto and inclusive of the 30th June, 1979.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulation, 1950.

(2) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulaions, 1959 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory ;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment,

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S. 38014/41/78-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 मई, 1979

का० आ० 1767.—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि किसी भी तेल क्षेत्र में सेवाओं को, जिन्हें उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में प्रविष्टि 17 द्वारा शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिये ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (न) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस० 11017/4/78-डी० आई० (ए)]

एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 10th May, 1979

S.O. 1767.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that services in any oil field which are covered by entry 17 in the First Schedule to the said Act, should be declared to be public utility services for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the said services to the public utility services for the purposes of the said Act for a period of six month.

[No. S. 11017/4/78/DI(A)]

L. K. NARAYANAN, Desk Officer.

नई दिल्ली, 10 मई, 1979

का० आ० 1768.—खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० शंकरन, उप महानिदेशक खान सुरक्षा (पूर्वी क्षेत्र) सीतारामपुर, को श्री बी० एम० भट्ट, जो प्रतिनियुक्ति पर विदेश जा रहे हैं, के स्थान पर, ऐसे सभी क्षेत्रों के लिए जिस पर उक्त अधिनियम का विस्तार है, 11 मई, 1979 से 20 मई, 1979 तक मुख्य खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० ए-11019/1/79-एम०-I]

मीना गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 10th May, 1979

S.O. 1768.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) the Central Government hereby appoints Shri S. Sankaran, Deputy Director General of Mines Safety (Eastern Zone) Sitarampur, to be the Chief Inspector of Mines for all the territories to which the said Act extends, on and from the 11th May, 1979 until 20th May, 1979 vice Shri B M. Bhat, who is proceeding on deputation abroad.

[No. A. 11019/1/79-MI]

MEENA GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 मई, 1979

का० आ० 1769.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 16 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री पी० एस० हबीब महम्मद को 7 मई, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश जारी होने तक श्री के० डी० मदान जो छुट्टी पर चले गये हैं, के स्थान पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या ए० 12026/1/78-एच० आई०)]

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 17th May, 1979

S.O. 1769.—In pursuance of Section 15 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government appoints Shri P. S. Habeeb Mohamed, I.A.S. as Director General of Employees' State Insurance Corporation, with effect from the forenoon of the 7th May, 1979, until further orders vice Shri K. D. Madan proceeded on leave.

[File No. A-12026/1/78-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979